(b) if so, what are the details thereof;

(c) how many Sri Lankan Tamils have obtained Indian citizenship and how many of them are of Indian origin; and

(d) whether Sri Lankan Tamils have gone to courts for the grant of Indian citizenship and if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS: (SHRI RAJESH PILOT): (a) to (c) Sri Lankan Tamil refugees who arrived in India in July 1983 or after are not granted citizenship except in the case of those Sri Lankans who are married to Indian citizens and arrived in India on valid travel documents, for a bonafide purpose, subject to fulfilling the statutory requirements under the Citizenship Act/Rules. Since July 1983, 114 Sri Lankans have been granted citizenship under this category.

(d) No information is available with the Central Government about any Sri Lankan Tamil refugee having gone to the court for grant of Indian citizenship.

Handing over of DTC to Government of National Capital Territory of Delhi

1528. SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are contemplating to hand over the Delhi Transport Corporation to Government of National Capital Territory of Delhi;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) whether it is a fact that the fleet of buses owned by Delhi Transport Corporation has gone down considerably; if so, what are the reasons therefor and the steps Government are contemplating to bring DTC out of red?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Yes, Sir.

(b) As Delhi has become a Union Territory with a separate Government, Government of National Capital Territory of Delhi was requested to accept the transfer of DTC. However, Govt. of National Capital Territory of Delhi have raised a number of conditions before accepting the transfer of DTC.

(c) Yes, Sir. Due to various financial and other constraints, DTC is not in a position to operate its full fleet of buses. The Government has taken the following steps to improve the financial position of D.T.C.:—

1. Introduction of Voluntary Retirement Scheme in order to reduce its surplus staff.
2. Reduction in manpower ratio.
3. Ban on recruitment.
4. Realistic balance of loss making and profit earning routes being made on continuous basis.
5. Grant of additional funds to bring on road about 1000 buses lying idle for minor repairs etc.

आई. एस. आई. की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु कदम

1529. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत की पश्चिमी सीमा पर आई. एस. आई. की उन गतिविधियों के बढ़ने के संबंध में ब्यौरा क्या है जो प्रकाश में आई है;

(ख) पंजाब तथा राजस्थान सीमा पर कांटेदार बाड़ लगाने और फ्लड लाईट लगाने का कितना काम हो गया है और बाकी बचे काम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आई. एस. आई. की गतिविधियों को रोकने के लिए और कौन से कदम उठाए गए है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) आसूचना रिपोर्टों से पश्चिमी सीमा पर आई. एस. आई. की गतिविधियों में कुछ बढ़ोत्तरी का पता चलता है। एक उल्लेखनीय घटना, राजस्थान में सीमा सुरक्षाबल द्वारा कुख्यात आतंकवादी नवतेज सिंह को पकड़ने की है। उसके साथी कमलजीत सिंह ने साइनाईड कैपसूल खा लिया था। बताया जाता है कि नवतेज और उसके साथी ने आई. एस. आई. की सहायता से भारत में घुसपैठ की थी।

(ख) पंजाब सीमा और राजस्थान के गंगानगर और बिकानेर सेक्टर में तेज रोशनी की व्यवस्था करने और तारों की बाड़ लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर सेक्टर में यह कार्य चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। प्रथम चरण में, जैसलमेर सेक्टर में 121 किलोमीटर क्षेत्र में तेज रोशनी की व्यवस्था और तारों की बाड़ लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

बाड़मेर सेक्टर में द्वितीय चरण के अधीन 146 किलोमीटर क्षेत्र में और तृतीय चरण के अधीन 120 किलोमीटर क्षेत्र में कार्य चल रहा है और इस कार्य को क्रमशः दिसम्बर, 1995 और जून, 1996 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) पश्चिमी सीमा पर आई.एस.आई. की गतिविधियों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें स्वीकृत की गयी हैं।

(ii) गश्त/नाकाबंदी को गहन किया गया है।

(iii) जीपें और मोटर साईकिलें उपलब्ध कराके सीमा गश्त गहन की गयी है।

(iv) नये और अतिरिक्त निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है।

(v) सीमा पर सर्तकता बढ़ाने के लिए दूरबीन, गोगल, टिन-टेलिस्कोप, पी.एन.वी. दूरबीनें और हाथ से पकड़ने वाली सर्च लाईटें उपलब्ध करायी गई हैं।

(vi) नदी तटीय क्षेत्रों की गश्त के लिए बोट/मोटर-बोट उपलब्ध करायी जा रही है।

(vii) वाहनों से गश्त लगाने के लिए सीमा सड़क/रास्तों का निर्माण/विकास किया जा रहा है।

(viii) सीमा पर गहन निगरानी रखने के लिए राज्य/केन्द्रीय सतर्कता तंत्र को सुचारू बनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत किया जाना

1530. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी**: क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल, 1994 से आज तक गुजरात में किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने, उनका विस्तार करने और मरम्मत करने का कार्य शुरू किया गया है और गुजरात से गुजरने वाले शेष राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसा कार्य कब तक शुरू किया जाएगा; और

(ख) अनुमानित खर्च का ब्यौरा क्या है और इस पर वास्तव में कितना धन खर्च किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 अहमदाबाद-बम्बई खंड के चुनिंदा खंडों को चौड़ा करने का कार्य 1.4.94 के बाद प्रारंभ हो चुका है। वार्षिक योजना (1995-96) में रा.रा. सं. 8 और 8 ग के चुनिंदा खंडों को चार लेन का बनाने के लिए प्रावधान है। रा.रा. 8 ग पर इस कार्य के लिए मंजूरी दे दी गई है और कार्य अभी प्रारंभ होना है। गुजरात सहित देश में किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) केन्द्र सरकार विकास और रख-रखाव के लिए निधियों का आबंटन राज्य-वार करती है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग वार। वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव हेतु गुजरात राज्य के लिए किया गया आबंटन इस प्रकार है:-

वर्ष	विकास	रख रखाव/मरम्मत
		(लाख रु.)
1994-95	7098.00	1316.64
1995-96	4600.00 (पुल शुल्क निधिको छोड़कर)	611.50 (जून, 1995 तक)

Telephone Connections on Demand

1531. DR. GOPALRAO VITHALRAO PATIL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government propose to provide telephone connections of all categories on demand by January 1997;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons for making promises at Public meetings;

(c) whether Government propose to provide all other facilities of Telecommunications sector to people on demand by January 1997; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) and (b) No, Sir. The National Telecom Policy 1994 announced by the Government envisages provision of telephone connections on demand by 1997 for which investment from Private Sector is also being sought.

(c) and (d) As per National Telecom Policy, various value added services will also be promoted for investment by the Private Sector.